विश्लेषण **युवाओं पर सरकार ने ध्यान दिया है, बजट बेहतर है, अब इसे जमीन पर उतारना चुनौती**

शिक्षा पर ध्यान मगर बजट वृद्धि जरूरी

विशेषज्ञ टिप्पणी

-प्रो क्षितिज भूषण दास
कुलपति, केंद्रीय विवि झारखंड

हेमंत सोरेन सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। वित्तमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी है। बजट को दूरगामी बनाने का प्रयास किया है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ किए जाने का एलान किया गया है। छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के साथ जिला पुस्तकालय की स्थापना होगी। इसके अलावा ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा बेशक सरकार का अच्छा कदम है। स्कूली शिक्षा पर भी 11607 करोड़ 67 लाख खर्च करने की योजना है, जो कि कुल बजट का 10 प्रतिशत ही है। इसे कम से कम 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की जरूरत है। इससे बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

रांची में मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए रीडिंग रूम का निर्माण भी सराहनीय कदम है। डिजिटल हो चले इस युग में आमजनों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी डिजिटली हमें जोड़ना होगा। ताकि आगामी दस वर्षों की रूपरेखा तैयार की जा सके। इसके लिए हमें उसी के अनुरूप बजट भी तैयार करना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय बजट पेश किया गया है। सभी जिलों में 300 बेड के अस्पताल को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य में 27 प्रतिशत की वृद्धि स्वागतयोग्य है। राज्य सरकार अब बायो गैस को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। वहीं श्रम नियोजन समेत जनजातीय विकास पर भी बजट में भी प्रविधान किया गया है। 590.70 लाख रुपये का प्रस्ताव सरना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ का प्रस्ताव समेत इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर है। कोरोना कहर के मद्देनजर एयर एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी बेहतर कदम है। इसके अलावा जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़, मनरेगा में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य और आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को सुविधा की बात सरकार को विकासशील बनाएगी। कुल मिलाकर यह बजट सराहनीय है।